eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

वैश्विक दक्षिण एशिया के प्रति भारतीय विदेश नीति (प्रधानमन्त्री पी0वी0 नरसिंहराव के प्रधानमन्त्रित्व काल में)

[1]**डा0 दीपक सिंह**

[1]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय स्ना0 महा0 चरखारी महोबा उ0प्र0

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

स्वतन्त्रता के बाद प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की विदेश नीति स्वतन्त्र दृश्टिकोण और गुटनिरपेक्षता की रही है, विश्व शान्ति को बनाए रखना, युद्ध की सम्भावनाओं को टालना, विवादों का मध्यस्थता या पंच–निर्णय द्वारा निपटारा करना, जातिभेद, रंगभेद और साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना विदेष नीति के लक्ष्य रहे हैं। नेहरू ने किसी तरह के क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण तथा विस्तार करने में रूचि नहीं ली विश्व के दो गुटों में बंट जाने से भारत ने किसी भी गुट के साथ रहने में रूचि नहीं ली तथा दोनों से (अमेरिका, सोवियत संघ) समान दूरी बनाए रखा तथा गुटों से अलग गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा। प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी नेहरू की विदेश नीति का पालन करते हुए किसी प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का समर्थन नहीं किया किन्तु प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के कार्यकाल (1971) में भारत–सोवियत मैत्रीसन्धि की गई तथा इसके बाद क्षेत्रीय संगठनों की महत्वा को स्वीकार किया जाने लगा तथा इसी क्रम में सार्क जैसे संगठनों की स्थापना हुई, यह दक्षिण एशिया के सात पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरूआत थी।

मुख्य शब्दावली– वैश्विक दक्षिण एशिया, भारतीय विदेश नीति, प्रधानमन्त्री पी0वी0 नरसिंहराव प्रधानमन्त्रित्व काल, विश्व राजनीति, क्षेत्रीय सहयोग।

प्रस्तावना

20 जून, 1991 को पी0वी0 नरसिंहराव अल्पमतीय सरकार का नेतृत्व करने के लिए चयन किए गए तथा माधव सिंह सोलंकी सरकार में विदेशमन्त्री बनाए गए। प्रधानमन्त्री पी0वी0 नरसिंहराव ने भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों को सामान्य बनाने पर बल दिया, इसके लिए दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों की छः बार अलग–अलग स्थानों तथा अवसरों पर बैठकें हुईं, परन्तु कोई विशेष सफलता न मिली। 30 जून, 1992 को एक वर्श का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद प्रधानमन्त्री राव

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

ने कहा ''यद्यपि अपने पड़ोसियों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में हमारी गहरी दिलचस्पी रंग ला रही है तथापि पाकिस्तान के साथ हमारा अनुभव निराशाजनक है।'' हम यही कथन अधिक बलपूर्वक 1991–98 तक के वर्षों के लिए भी दोहरा सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के उग्रवादियों को समर्थन तथा उन्हें दी जा रही सहायता के साथ–साथ 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय पाकिस्तानी शासकों के भारत विरोधी प्रचार पाकिस्तान के अड़ियल तथा भारत विरोधी रूख ने उत्तर शीत युद्ध काल में भारत–पाक के मध्य सम्भावित सहयोग तथा मित्रता की समस्त प्रक्रिया व्यर्थ कर दी। हरारे राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमन्त्रियों ने भविष्य में परिपक्व राजनीतिक सम्बन्धों तथा सूझ–बूझ के साथ काम करना स्वीकार किया। 06 दिसम्बर, 1992 की अयोध्या दुर्घटना के बाद से पाकिस्तान विवादास्पद ढांचे के गिराए जाने को लेकर मुस्लिम देशों को अपने पीछे लगाने में जुटा रहा, भारत को ''हिन्दू भारत'' के रूप में प्रस्तुत करके उसे एक मुसलमान विरोधी देश प्रस्तुत करता रहा।

जून, 1991 को भारत एवं श्रीलंका के विदेश मन्त्रियों माधव सिंह सोलंकी तथा हैराल्ड हर्थ के मध्य एक संयुक्त आयोग बनाने का समझाौता हुआ।[1] इस आयोग की बैठक 6 जनवरी, 1992 को सम्पन्न हुई जिसमें श्रीलंका के विदेष मन्त्री हैरोल्ड हर्थ ने यह घोशणा की कि लगभग 30000 तमिल शरणार्थियों को प्रथम चरण में स्वदेश वापस लाया जायेगा।[2] अप्रैल, 1992 में भारत–श्रीलंका सम्बन्धों को तब एक गहरा आघात लगा, जब राश्ट्रपति प्रेमदासा ने भारतीय शान्ति सेना को व्यवसाय करने वाली सेना करार दिया इधर राजीव गांधी की हत्या के बाद लिट्टे के प्रति तमिलनाडु की सहानुभूति समाप्त हो चुकी थी। गृहमन्त्री एस0बी0 चौहान ने लिट्टे को अवैध संगठन घोशित कर दिया तथा 14 मई, 1992 को भारत ने प्रतिबन्ध लगा दिया। 22 जून, 1993 को श्रीलंका के प्रधानमन्त्री रानिल विक्रम सिंघे भारत की यात्रा पर आए 21 सितम्बर, 1993 को उड्डयन क्षेत्र में एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने श्रीलंका जाने वाली उड़ानों की संख्या में वृद्धि का निर्णय लिया लेकिन भारत कुछ कारणोंवश इसे पूरा न कर सका। 16 अगस्त, 1994 को श्रीलंका में सिरिमावों भण्डारनायके की पुत्री चन्द्रिका कुमार तुंगे को चुनावों में जीत मिली तथा प्रधानमन्त्री बनीं। ''शान्ति की स्थापना की दिशा में पहल करते हुए प्रधानमन्त्री चन्द्रिका कुमार तुंगे ने जाफना, पेनिनसुला जाने वाले मालवाहक विमानों पर लगी पाबन्दी को हटा लिया जिसे तमिलों को अत्यन्त राहत मिली।''[3] 9 नवम्बर, 1994 को चन्द्रिका कुमार तुंगे ने चुनावों में विजय प्राप्त की तथा चौथी राष्ट्रपति बनीं तथा लिट्टे के साथ बातचीत के द्वारा समस्या के समाधान का रास्ता

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

अपनाया। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पी0वी0 नरसिंहराव ने श्रीलंका के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध कायम किए तथा श्रीलंका से भारत द्वारा भारी मात्रा में वस्तुओं का आयात भी किया। इस प्रकार प्रधानमन्त्री नरसिंहराव सरकार के कार्यकाल में भारत–श्रीलंका सम्बन्धों को एक नई दिशा प्राप्त हुई। ''प्रधानमन्त्री नरसिंहराव द्वारा साप्टा तथा साफ्टा की स्थापना पर विशेष जोर देकर श्रीलंका के साथ आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाया।''[4]

भारत में नरसिंह राव की सरकार बनने तथा बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुर्नस्थापना (सितम्बर, 1991) तथा बेगम खालिदा जिया के प्रधानमन्त्री बनने से दोनों देषों में मधुरता बढ़ी। बांग्लादेश के विदेश मन्त्री भारत के विदेष मन्त्री के आमन्त्रण पर अगस्त, 1991 को सरकारी यात्रा पर आए तथा एक ऋण करार तथा दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए। नदी जल बंटवारे पर अक्टूबर, 1991 में नई दिल्ली में और फरवरी, 1992 मे ढाका में सचिव स्तर की बातचीत प्रारम्भ हुई। मई, 1992 में खालिदा जिया ने भारत की यात्रा की और त्रिपुरा में 50 हजार चकमा शरणार्थियों की वापसी तथा अनाधिकृत आवागमन की समस्या से निपटने के लिए एक विदेश सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमत हो गए। 26 जून 1992 को भारत ने तीन बीघा क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तान्तरित कर दिया। तीन बीघा क्षेत्र को बांग्लादेश को पट्टे पर देने का भारत के कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया किन्तु बांग्लादेश के साथ मैत्री को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने ऐसा किया जो सही प्रतीत होता है। नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कोइराला ने 5 से 10 दिसम्बर, 1991 में भारत दौरे पर आए तथा पांच महत्वपूर्ण सन्धियों एवं करारों पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल ने 48 संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन किया अप्रैल, 1995 में नेपाली प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी की भारत यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाया। नेपाल का महत्व भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ''महाभारत के वन पर्व में भीम द्रोपदी के लिए कमल पुश्प की खोज में नेपाल के हिमालय की उपत्यकाओं में घूमे थे।''[5] ''भारत एवं नेपाल इतिहास, भूगोल, रिश्ते, धर्म, विश्वास, सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाध्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा होता हुआ भी नेपाल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है तथा भारत एवं चीन के बीच मध्यवर्ती देश की भूमिका में होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है।''[6] इस कारण से भारत को नेपाल के साथ आन्तरिक लगाव है एवं उसके प्रति नीति हमेशा सहयोगात्मक एवं सामंजस्यपूर्ण बनाये रखना भारत के हित में है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी दिसम्बर, 1991 में भूटान गए। भूटान के महामहिम नरेष वांगचुक ने जनवरी, 1993 तथा दिसम्बर, 1994 में भारत की यात्रा की। प्रधानमन्त्री नरसिंह राव ने 21–22 अगस्त, 1993 को भूटान की यात्रा की तथा यह यात्रा लाभप्रद रही तथा इससे भूटान में चल रही कई परियोजनाओं के सहयोग को बढ़ाने में मदद मिली। इस तरह भारत के द्वारा सहयोगात्मक रूख अपनाकर भूटान को हर तरह से सहायता पहुंचाने की नीति पर काम करते हुए उसको भी सभी राष्ट्रों के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया जिससे भारत की उदारता एवं लोकतन्त्रात्मकता का परिचय मिलता है। कुल मिलाकर प्रधानमन्त्री नरसिंह राव के द्वारा अपने पड़ोसियों के प्रति सहयोगात्मक, संवेदनात्मक, पारस्परिक, यथार्थपरक सम्बन्ध बनाने के प्रयास किए गए जिसमें कुछ एक तत्वों को छोड़कर उनकी विदेश नीति दक्षिण एशिया के देशों के प्रति सफल कही जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

(1) एशियन रिकार्ड, 1991, पृ0: 21939

(2) आर, के दुबेः इण्डिया–''श्रीलंका रिलेषन्स विद स्पेशल रिफरेन्स टू द तमिल प्राब्लम'', पृ0: 92–93

(3) फ्रन्टलाइन, 23 सितम्बर,1994

(4) इण्डियाज फॉरेन पॉलिसीः इमर्जिंग चैलेन्ज एण्ड पैराडिम्स, बी.सी.उपरोती, एस.एन. कौशिक मोहनलाल शर्मा, कलिंगा पब्लिकेषन, 2003 पृ0:395

(5) डॉ0 रामदेव भारद्वाजः भारत और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2005, पृ0–344

(6) सिविल सर्विसेज क्रानिकल, फरवरी, 2007 पृ0–23

(7) (पी0वी0) नरसिंहराव एवं दक्षिण एशिया